केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 347 सोमवार 13 जुलाई 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

भाजपा जिलाध्यक्ष पर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी मामले में युवक पर मुकदमा दर्ज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा जिला महामंत्री अमृत कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान गोंडा के ग्राम नेवारी, पोस्ट दर्जी कुआं निवासी भरत सिंह के रूप में हुई है। आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हरैया दौरे के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र के लेटर पैड पर मंच पर बैठने वाले नेताओं की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।

इसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में आरोपी ने जिलाध्यक्ष के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में नाराजगी फैल गई। भाजपा जिला महामंत्री अमृत कुमार वर्मा ने मामले में कोतवाली थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोतीचंद ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई 47.52 लीटर शराब

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती।रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीम ने रविवार, 12 जुलाई 2026 को बस्ती रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई की। सुबह करीब 5रू35 बजे बिहार में तस्करी के लिए ले जाई जा रही 47.52 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस दौरान दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जब्त शराब की कीमत लगभग 34,320 रुपये आंकी गई है।

यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत की गई। आरपीएफ पोस्ट बस्ती के प्रभारी निरीक्षक राशिद बैग मिर्जा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक कमलेश कुमार यादव, सहायक उपनिरीक्षक गुलाम वारिस सिद्दीकी, हेड कांस्टेबल राजकुमार और कांस्टेबल देवेंद्र कुमार सिंह की टीम जीआरपी बस्ती के कांस्टेबल कृष्णानंद सिंह के साथ स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी।

मुखबिर की सूचना पर टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर–3 के पश्चिमी छोर से दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। उनकी तलाशी लेने पर गुलाबी रंग के पॉलिथीन बैग में रखे तीन गत्तों से ऑफिसर्स च्वाइस व्हिस्की के कुल 264 टाट्रा पैक (प्रत्येक 180 मिलीलीटर) बरामद हुए। शराब को छिपाने के लिए गत्तों के ऊपर नए लेडीज सूट रखे गए थे।

पूंछताछ में आरोपितों ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के कारण वे ट्रेन से यह शराब बरौनी ले जाकर अधिक दाम पर बेचने की तैयारी में थे। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान शिवदास (46) निवासी बरगदवा, थाना सोनहा, और राजू (33) निवासी कोठिली, थाना सोनहा, जनपद बस्ती के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। आरपीएफ ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों आरोपितों और बरामद शराब को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी बस्ती के सुपुर्द कर दिया है।

यूपी में भ्रष्ट अफसरों पर गिरेगी गाज, बड़ी कार्रवाई की तैयारी

लखनऊ (आभा)। यूपी सरकार भ्रष्टाचारियों पर और शिकंजा कसने जा रही है। सेवानिवृत्त एआरटीओ ललित कुमार के घर छापेमारी में मिले 35 करोड़ रुपये की चल–अचल संपत्ति सामने आने के मामले को उच्च स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस जांच में भ्रष्टाचार को लेकर मिले पुख्ता सुबूत वालों के खिलाफ बडी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यूपी में इस तरह की जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

विजिलेंस की खुली जांच में आय से अधिक संपत्ति के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसने के साथ ही लटके मामलों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। उच्च स्तर पर विजिलेंस भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच कर रही है, उनमें गंभीर श्रेणी के कई मामलों की प्रगति भी पूछी गई है। सूत्रों का कहना है कि आय से कई गुना संपत्ति जुटाने वाले कुछ अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। शासन इन कार्रवाई के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मियों को बड़ा संदेश देने का प्रयास करेगी। वहीं विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी लंबित शिकायतों की जांच में भी तेजी आएगी।

विजिलेंस ने लखनऊ में रिटायर एआरटीओ ललित कुमार के घर पर छापेमारी के दौरान 13 किलो सोना और 1.62 करोड़ रुपये नगद समेत 20 करोड़ की संपत्ति बरामद की थी। उनकी कुल 35 करोड़ रुपये की चल–अचल संपत्ति सामने आई थी, जिसका आगे की जांच में और बढ़ना तय माना जा रहा है। विजिलेंस ने छापेमारी में बरामद संपत्तियों के कई दस्तावेजों की अभी पड़ताल की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में बनी रणनीति, अधिवेशन पर विमर्श

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट जिला इकाई की बैठक जिला अध्यक्ष अजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गांधीनगर स्थित एक सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में सदस्यता अभियान, आगामी गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में संगठन के प्रत्याशी राजीव यादव को जिताने की रणनीति, ब्लॉक संयोजकों की नियुक्ति, जनपद स्तर पर 30 जुलाई को होने वाले धरने में प्रतिभागिता और जनपदीय शिक्षक सम्मेलन कराने पर विचार विमर्श किया गया।

मुख्य अतिथि प्रदेश कोषाध्यक्ष विजेंद्र वर्मा और विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री धुव नारायण चौधरी ने कहा कि संगठन मिलकर राजकीय करण, सेवा सुरक्षा बहाली हेतु आंदोलन चलाएगा और प्रत्याशी राजीव यादव को चुनाव में भारी मतों से विजई बनाते हुए सदन में भेजने का काम करेगा।

बैठक में मंडलीय महामंत्री डॉ. श्रवण गुप्ता जनपदीय महामंत्री डॉ. सत्य प्रकाश मौर्य प्रवक्ता जिला प्रवक्ता बाबूराम वर्मा उपाध्यक्ष, सुरेन्द्र मणि मिश्र, रमेश वर्मा,सुनील मौर्य, रामभान, मीडिया प्रभारी नीरज वर्मा, विनोद प्रकाश वर्मा, सहित अनेकं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

शहर कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण सम्पन्न

-संगठन की मजबूती के लिये अभियान चलायें कांग्रेस पदाधिकारी- विश्वनाथ चौधरी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर शहर कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण सम्पन्न हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 'ज्ञानू' वरिष्ठ नेता देवेन्द्र श्रीवास्तव ने पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुये कहा कि शहर कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस के नीति, कार्यक्रमों से लोगों से जोड़े । संगठन की मजबूती से ही राजनीतिक, सामाजिक लक्ष्य हासिल होंगे।

शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शौकत अली नन्हू, उपाध्यक्ष मो. अकरम, शेष नरायन शुक्ल, किशन कुमार गोयल, विश्वजीत, निशान्त श्रीवास्तव, महादेव प्रसाद पाण्डेय, अख्तर हुसेन, सरवर अंसारी, हरीश कुमार गुप्ता, मो. नईम, रियाज अहमद महामंत्री, लालजी शर्मा, अमित कुमार श्रीवास्तव, मो. अहमद, मो. शैफ अली, दाउद अहमद, मो. नसीम, मो. इमरान, देवाशीष शुक्ल, हरिश्चन्द्र, शाहिद अब्बास सचिव ने शपथ ग्रहण किया। पदाधिकारियों में नियुक्ति पत्र वितरित किया।

शपथ ग्रहण के बाद शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शौकत अली नन्हू ने कहा कि संगठन को सभी वार्डो में सक्रिय करने के साथ ही सम्पर्क अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों, मंहगाई, श्रीराम मंदिर में चंदा चोरी, यूजीसी से नाराज लोग तेजी से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से डा. वाहिद अली सिद्दीकी, अलीम अख्तर, संदीप श्रीवास्तव, जयंत चौधरी, मो. रफीक खान, गंगा मिश्र, जमील अहमद, सुनील पाण्डेय, फिरोज खान, सर्वेश शुक्ल, आनन्द निषाद, संजीव त्रिपाठी के साथ ही कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट की मांग, सांसद को सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट दिए जाने की मांग को लेकर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को सांसद राम प्रसाद चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह एवं जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा के नेतृत्व में दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के प्रावधानों तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के संबंध में उपलब्ध कानूनी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ऐसे शिक्षकों को टीईटी से छूट मिलनी चाहिए। इस संबंध में केन्द्र सरकार से आवश्यक निर्णय कराने की मांग की गई।

-शिक्षकों की मांगों को संसद तक ले जाएंगे -राम प्रसाद चौधरी

ज्ञापन लेने के बाद सांसद राम प्रसाद चौधरी ने शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह विषय लाखों शिक्षकों के हितों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि वह इस विषय को पार्टी की बैठक में प्रमुखता से उठाएंगे तथा संसद में भी इस मुद्दे को उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने कहा कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति तत्कालीन नियमों के अनुसार हुई थी। ऐसे शिक्षकों को टीईटी से छूट मिलनी चाहिए। यह मांग पूरी तरह कानूनी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित है। जिला मंत्री ने कहा कि संगठन लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहा है। हमारा उद्देश्य पूर्व नियुक्त शिक्षकों को न्याय दिलाना है। सांसद द्वारा दिए गए आश्वासन से शिक्षकों में उम्मीद जगी है कि सरकार इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेगी। कोषाध्यक्ष दुर्गेश यादव ने कहा कि शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करना संगठन की प्राथमिकता है। हमें विश्वास है कि सरकार उपलब्ध कानूनी साक्ष्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर टीईटी से छूट का निर्णय लेकर शिक्षकों को राहत देगी।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से गिरजेश सिंह, बब्बन पाण्डेय, चंद्रशेखर पाण्डेय, श्रीधरपाल, सोहन यादव, अश्विनी पाण्डेय, धर्मराज यादव, दीपचंद, मोहम्मद असलम, अनुराग श्रीवास्तव, नवीन सिंह, विनय पाण्डेय, तरुण कुमार, सुरेंद्र यादव, संजय यादव, सुरेन्द्र यादव, राम पियारे, लक्ष्मण लाल, शुभम चौधरी, प्रवीण श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार पाण्डेय, मुरलीधर, राहुल राणा, प्रकाश कुमार गौतम, विजय यादव, संजय चौधरी, राजीव सिंह, राजकुमार श्रीवास्तव, अनीस अहमद, अनिल पाठक, अशोक यादव, आशीष दुबे, रजनीश यादव, हरेंद्र यादव, सुधीर तिवारी, गौरव चौधरी, विवेक सिंह, बीपी आनंद, शिवशंकर यादव, प्रशांत द्विवेदी, रामगोपाल मौर्य, लालचंद, महादेव वर्मा, महेंद्र चौधरी, सुमित्रानंदन, विनोद चौधरी, राकेश , परमानंद, सच्चिदानंद, मंगला मौर्य, सुरेश गौड, उमाकांत शुक्ल, मो असलम, मक्खन लाल, सतीश चंद्र यादव, कविन्द्रनाथ चौधरी,शिवशंकर यादव, अशोक कुमार पांडेय, सुरेन्द्र चौधरी,विनोद कुमार चौधरी,हृदय विकास पांडेय, बृजेश त्रिपाठी, डा० अनूप कुमार सिंह, ओंकार चौधरी, अजय सिंह, रामगोपाल यादव, राजितराम यादव, नरोत्तम सिंह, अंकित सिंह, रामभवन, जितेंद्र, सुनील पाण्डेय, प्रमोद सिंह, शत्रुजीत यादव, रामशंकर लाल, जितेंद्र पाण्डेय, रामललित, विजय, राकेश यादव,अखिलेश पाण्डेय, मुरलीधर, प्रकाश अम्बेडकर आदि शामिल रहे।

गौर थाना के हेडकांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गौर थाना में तैनात दीवान अरुण कुमार मिश्रा की मौत हो गई। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर मकान मालिक की सूचना पर साथी पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौर ले गए। प्राथमिक परीक्षण के बाद उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाना परिसर में शोक का माहौल छा गया। हेड कांस्टेबल अरुण कुमार मिश्रा वर्ष 1994 बैच के सिपाही थे। वर्तमान में गौर थाना में तैनात थे। उनकी पोस्टिंग 28 अगस्त 2025 को गौर थाना में हुई थी।

वह मूल रूप से बहराइच जिले के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के मधिनगरा गांव के निवासी थे। बताया जाता है कि वह थानाक्षेत्र के चकचई

चौराहे के पास मुन्ना शुक्ला के मकान में किराये के कमरे में रहते थे। रविवार सुबह 10 बजे तक दरवाजा नहीं खुलने पर मकान मालिक ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा न खुलने पर मकान मालिक ने गौर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही साथी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दरवाजा खोलकर उन्हें तत्काल सीएचसी गौर ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी ली। गौर थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान ने मृतक के परिजनों को दूरभाष पर सूचना दी, जिसके बाद बहराइच स्थित उनके घर में कोहराम मच गया। परिजन बस्ती के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।

हरैया तहसील के 21 लेखपालों का तबादला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हरैया तहसील क्षेत्र में लंबे समय से एक ही हल्के पर तैनात 21 लेखपालों का स्थानांतरण एसडीएम हरैया उमाकांत तिवारी ने कर दिया। बताया जा रहा है कि स्थानांतरण सूची जारी होने के बाद कुछ लेखपाल आदेश रुकवाने के प्रयास में जुटे हैं, जबकि कई एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। एसडीएम उमाकांत तिवारी ने बताया कि जिन लेखपालों का स्थानांतरण किया गया है, वे तीन–चार वर्षों से एक ही हल्के पर कार्यरत थे। साथ ही कुछ लेखपालों के संबंध में किसानों से लगातार शिकायतें भी मिल रही थीं। उन्होंने कहा कि जनहित, प्रशासनिक जरूरतों और शासकीय कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से स्थानांतरण किया गया है।

जिन लेखपालों का स्थानांतरण किया गया है, उनमें आशीष पाठक फेरता से सिधौर, धर्मेंद्र वर्मा महराजगंज से फेरता, मुकेश कसौधन रिधौरा से रामवापुर, सौरभ पांडेय रामापुर से रिधौरा, अजयराज सिंह बैजलपुर से महादेवरी, संतोष उपाध्याय विक्रमजोत से दुबौलिया, सपना सिंह गौरियानैन से विक्रमजोत, सुधा यादव दुबौलिया से गौरियानैन, दुर्गेश पांडेय सिकंदरपुर से फूलडीह, सरिता शुक्ला बड़ेरिया बाबू से लीलापुर, वीरू सिंह अमौली से बैजलपुर, अमित कुमार हंस बिछैया पांडेय से सोनहटी, विजय मौर्य नेवरी रामबक्स से हैदराबाद, श्रीप्रकाश पांडेय हैदराबाद से मुसहा बरहपेड़ा, शुभम सेन बछईपुर से नरथरी, दुर्गेश द्विवेदी केशवपुर से बछईपुर, उगन्नाथ उपाध्याय रजौली से खान कला, सुभाषचंद्र यादव खान कला से दुबौलिया, प्रभात यादव अकवारा से कोलंबिया, शशिधर मिश्रा किशुनपुर से खंडवा कुंवर और राजकिशोर यादव जाटवलिया से किशुनपुर शामिल हैं।

तौआब अली तीसरी बार जिला संयोजक घोषित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रविवार को अटेवा पेंशन बहाली मंच की बैठक गांधीनगर के निकट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में अटेवा प्रदेश नेतृत्व के क्रम मे आगामी कार्यक्रमों की सफलता हेतु रणनीति तय करने के ही जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी किया गया। मण्डलीय महामंत्री दीपक सिंह प्रेमी के देखरेख में जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से तौआब अली को तीसरी बार जिला संयोजक और कैलाश नाथ को महामंत्री, अमर चन्द को कोषाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। इसी क्रम में हरिकृष्ण, सुनील मौर्या, अमरनाथ,जितेंद्र वरुण को जिला उपाध्यक्ष, श्रीनाथ विश्वकर्मा, ज्ञानेन्द्र भारती, राकेश सिंह को जिलामन्त्री घोषित किया गया।

-कार्यकारिणी का पुर्नगठनः टेट, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष पर जोर

जिला प्रवक्ता पद पर विनोद प्रकाश वर्मा एवं जिला संयुक्त मंत्री के पद पर अब्दुल कयूम, संतोष कुमार यादव,हरिसिंह, और अवधेश कुमार वर्मा का मनोनयन हुआ।इसी तरह मोहम्मद सलाम, डॉ वीरेंद्र चौधरी, जावेद इकबाल, राजेश यादव,उमेश चंद्र राव को जिला संगठन मंत्री,नीरज वर्मा को जिला मीडिया प्रभारी, मनीष प्रकाश मिश्र को जिला आई टी सेल प्रभारी, बृजेश कुमार, अब्दुल मामूद को जिला सलाहकार पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई। जिला संरक्षक पद पर प्रमोद ओझा, बृजेश वर्मा और देवेंद्र तिवारी को मनोनीत किया गया। डॉ. गरिमा वर्मा को जिला महिला संयोजक ,अनीता प्रजापति को जिला संरक्षक, सिकन्दर , पंकज अग्रहरि और शिवाजी को जिला कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया।

मनोनयन के उपरांत जिला संयोजक तौआब अली ने सरकार से मांग किया कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले के शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाय एवं शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए अन्यथा संगठन अगस्त माह में जिले पर और 25 सितम्बर को लखनऊ में बड़ा आन्दोलन करेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। कार्यक्रम में बिजेन्द्र वर्मा, ध्रुव नारायण चौधरी, अजय वर्मा, विनोद प्रकाश वर्मा, श्रवण गुप्ता, रमेश वर्मा, सुरेंद्रमणि मिश्र, डॉ. सत्य प्रकाश मौर्या आदि शिक्षक कर्मचारी शामिल रहे।

राशन कोटेदार ने लगाया जातिसूचक गाली, मारपीट, जान से मारने की धमकी का आरोप, दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दुबौलिया थाना क्षेत्र और कप्तानगंज विकास खण्ड के ग्राम पंचायत नरहरपुर के कोटेदार संजय कुमार ने गांव के एक व्यक्ति पर जातिसूचक गालियां देने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने तथा लगातार मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित ने थाना दुबौलिया में शिकायती पत्र देकर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है।

शिकायती पत्र में ग्राम पंचायत नरहरपुर, भटपुरवा, देवकीजोत के वर्तमान कोटेदार संजय कुमार का आरोप है कि गांव निवासी ग्राम प्रधान उदयभान चौधरी के पुत्र रणविजय चौधरी लगातार उनके विरुद्ध शिकायतें कराकर दबाव बनातें हैं और राशन वितरण में हस्तक्षेप करतें है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी द्वारा कथित रूप से राशन और रुपये

की मांग की जाती थी तथा मांग पूरी न होने पर उन्हें अनुसूचित जाति (चमार) होने के कारण जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है।

पीड़ित के अनुसार गत 7 जुलाई को राशन वितरण के दौरान रणविजय चौधरी ने एक लाभार्थी को दोबारा राशन देने का दबाव बनाया। इनकार करने पर आरोपी ने कथित रूप से जातिसूचक गालियां दीं, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया।

पीड़ित का यह भी आरोप है कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति का है और अब भी लगातार धमकी दे रहा है कि उसे सड़क दुर्घटना का रूप देकर जान से मार दिया जाएगा। उनका कहना है कि शिकायत देने के बावजूद अब तक पुलिस की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है।

पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि भविष्य में उनके या उनके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी आरोपी के साथ–साथ कार्रवाई न करने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों की भी होगी।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक **भारतीय बस्ती**

बस्ती 13 जुलाई 2026 सोमवार

सम्पादकीय

सरकारी स्कूलों से मोहभंग क्यों..?

तमाम विसंगतियों, संसाधनों की कमी, शिक्षकों का पर्याप्त संख्या में न होना तथा समय के साथ कदमताल न कर पाने वाले सरकारी स्कूलों से छात्रों का मोहभंग होना बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। देशभर में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं, छात्रों के प्रवेश व शिक्षकों के आंकड़ों पर नजर रखने वाले केंद्र के आंकड़ों से पुष्टि हुई कि छात्र सरकारी स्कूलों के विमुख हो रहे हैं और लगातार निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीते दो सालों में लगभग 86 लाख छात्र सरकारी स्कूल छोड़कर चले गए। वहीं इसी दौरान प्राइवेट तथा बिना सरकारी मदद वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों में 88 लाख नए छात्र शामिल हुए हैं। 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस' के अनुसार शुरुआती कक्षा से सेकेंडरी स्तर तक स्कूल में दाखिले में कमी देखी गई है। जो संख्या साल 2023–24 के 24.8 करोड़ से घटकर साल 2025–26 में 24.72 करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में दाखिले तेजी से घटकर 12.75 करोड़ से 11.89 करोड़ हो गए हैं। वैसे ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि तमाम कमियों और घटती लोकप्रियता के बावजूद सरकारी स्कूल ज्यादतर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। निस्संदेह, ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये गंभीर प्रयास किए जाएं। यह हकीकत है कि जमीनी स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि अभी तक अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता का वायदा पूरा नहीं हो पाया है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि सेकेंडरी स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है। वहीं दूसरी ओर शून्य दाखिले वाले स्कूलों की संख्या 12,954 से घटकर 5,663 हो गई है। इसके साथ ही एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 1.11 लाख से घटकर 1.01 लाख हो गई है।

दूसरी तरफ अब शिक्षकों की कुल संख्या 1.03 करोड़ है, जिसके चलते छात्र–शिक्षक अनुपात 25 से घटकर 24 हो गया है। वहीं लड़कियों की भागीदारी भी बढ़कर 48.4 होना उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिये संरचनात्मक सुविधाएं, छात्राओं के लिये शौचालय, हाथ धोने तथा पीने के पानी की व्यवस्था में उत्साहजनक सुधार हुआ है। हालांकि, जमीनी स्तर पर दावों की हकीकत तार्किक कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। सही मायने में किसी सुविधा का उपलब्ध होना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना दो अलग चीजें हैं। लेकिन देश के नीति–नियंताओं को समझना चाहिए कि समाज में जिस वर्ग को शिक्षा की अधिक आवश्यकता है, वही सरकारी स्कूलों पर अधिक निर्भर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी अपनी मजबूरी के चलते सरकारी स्कूलों की ओर रुख करता है। इसके बावजूद कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गाहे–बगाहे सवाल उठाए जाते रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने हर बच्चे को अनिवार्य रूप से निरूशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने को कहा था तो आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में शिक्षा के ये लक्ष्य हासिल क्यों नहीं किए गए? यदि तब केंद्र व राज्य सरकारों ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये ईमानदार प्रयास किए होते और पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये होते तो आज लोगों को सरकारी स्कूलों से मोहभंग न हो रहा होता। यदि संपन्न वर्ग, अधिकारियों के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे एक साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते तो शिक्षा जगत में आज व्याप्त गहरी विसंगति की खाई दूर हो जाती। हमारे तंत्र द्वारा सरकारी स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति उदासीनता दिखाने, शिक्षकों को गाहे–बगाहे गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने और समय रहते पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति न करने से स्थितियां विकट हुई हैं। यह विडंबना ही कही जाएगी कि सत्तर के दशक में शिक्षा के उन्नयन के लिये गठित कोठारी आयोग की वह सिफारिश आज भी धूल फांक रही है, जिसमें शिक्षा पर देश के जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने का सुझाव दिया गया था। आर्थिक तंगी से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता व साख पर आंच आई है।

वामपंथ के शताब्दी वर्ष पर सन्नाटा

भारत में वामपंथ का शताब्दी वर्ष बिना किसी विमर्श के बीत गया। जो वामपंथी दल बात–बात पर दस्तावेज प्रकाशित करते थे, आज उनकी बौद्धिकता पर सन्नाटा छाया हुआ है। एक समय था, जब बीटी रणदिवे, भूपेश गुप्ता, पी. सुंदरैया, ईएमएस नंबूदरीपाद, हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे वाम नेताओं की लेखनी विमर्श को इस हद तक प्रभावित करती थी कि सत्ताधारी दल (कांग्रेस) को उसमें कूदने के लिए बाध्य होना पड़ता था। छोटी–छोटी घटनाओं पर भी सौ दस्तावेज आ जाते थे। मानवेंद्र राय पहले और अंतिम मार्क्सवादी थे, जिन्होंने दुनिया के वाम आंदोलन में अपनी जगह बनाई। वे सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता लेनिन को वैचारिक जवाब देने की पात्रता रखते थे। इसी क्रम में लेनिन की नापसंदगी हुई और वे रातों–रात 'प्रतिक्रियावादी' घोषित हो गए। जब वे लौटकर भारत आए, तो उनके समर्थन एवं विरोध में सैकड़ों दस्तावेज लिखे गए। दूसरी घटना वर्ष 1962 की है, जब भारत–चीन युद्ध को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी में 'कौन गलत, कौन सही' के सवाल पर दंगल हुआ। चीन की पक्षधरता को लेकर पार्टी के विचारक एक–दूसरे के आमने–सामने थे। इस पर दस्तावेजों की भरमार लग गई।

वर्ष 2025–26 वैचारिक–संगठनात्मक–चुनावी गिरावट पर गौर करने का अवसर था, जो अंधेरे में खो गया। जो बात वर्ष 1978 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल के सालकिया की बैठक में की थी, उसे दोहराने का नैतिक साहस अब उसमें शायद नहीं बचा है। तब पार्टी ने आत्मालोचन किया था और अपनी गिरावट के लिए तीन कारणों को रेखांकित किया था, जिसमें एक सार्वजनिक विमर्श के लिए उपयोगी था, जबकि दो अन्य पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी से जुड़े थे।

यह था 'बुर्जुआ अवगुणों' का पार्टी में समावेश। इसका अर्थ बताया गया कि भाई–भतीजावाद, भ्रष्टाचार, संसाधनों को एकत्रित करने की लालसा और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पार्टी की संस्कृति में संक्रमण। तब और अब में कितना अंतर आ गया है। आज पार्टी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के परिवार पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद उनके समर्थन में सड़कों पर है।

इस प्रदर्शन को राजनीतिक बचाव कहा जा सकता है। जब राजनीति और सामाजिक जीवन में मूल्यों का सामूहिक क्षरण होता है, तब वित्तीय अनियमितताओं, अनैतिक आचरणों और कुसंस्कृति के प्रत्यक्ष उदाहरणों को सार्वजनिक रूप से सही बताना पुरुषार्थ बन जाता है। और ऐसे पुरुषार्थी ही पुरस्कृत किए जाते हैं। यह तब होता है, जब शेष समाज अपने आपको तमाशबीन बना लेता है। ऐसे समय में विचार, दर्शन और मूल्यों की बात करना असंतुष्ट घोषित होने का जोखिम उठाना होता है। वामपंथ में इस जोखिम को उठाने वाले कभी बहुतायत में होते थे, वे अब नहीं दिखते।

विकास की धंसती सड़कें और भ्रष्टाचार

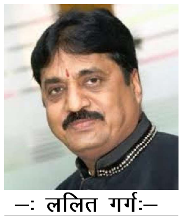

–: ललित गर्ग:–

जिस दिल्ली– देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को आधुनिक भारत के तेज, सुरक्षित और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसकी सड़क उद्घाटन के महज ढाई महीने बाद पहली ही बरसात में धंस गई। सड़क इस तरह धंसी कि कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया। प्रश्न यह है कि करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़क पहली ही वर्षा का सामना क्यों नहीं कर सकी? क्या निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया? क्या जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं थी? या फिर यह भ्रष्टाचार, लापरवाही और जवाबदेही के अभाव का परिणाम है? यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में नई सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों और सार्वजनिक भवनों के ध्वस्त होने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग एक दर्जन छोटे–बड़े पुलों का गिर जाना पूरे देश को झकझोर गया था। एक ही दिन पांच पुल–पुलियों का धराशायी होना केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि शासन–प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का जीवंत प्रमाण था। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की जान चली गई। कोलकाता के विवेकानंद फ्लाईओवर के गिरने से अनेक परिवार उजड़ गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल–1 की छत गिरने की घटना और मुंबई के घाटकोपर में विशाल होर्डिंग गिरने से हुई मौतों ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता गंभीर संकट से गुजर रही है।

इन घटनाओं को केवल प्राकृतिक आपदा या भारी वर्षा का परिणाम बताकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। यदि पहली ही बारिश में सड़क धंस जाए, पुल बह जाएं या भवनों की छतें गिर जाएं, तो यह प्रकृति की नहीं, बल्कि मानव निर्मित विफलता की एवं गहरे में पैठे भ्रष्टाचार की कहानी है। आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीक के इस युग में ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं। यह विकास नहीं, बल्कि विकास के नाम पर जनता के साथ किया गया विश्वासघात है। सड़कें और पुल किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति की धमनियां होते हैं। इनके माध्यम से व्यापार चलता है, गांव शहरों से जुड़ते हैं, किसान अपनी उपज बाजार तक पहुंचाते हैं और आम नागरिक सुरक्षित आवागमन करते हैं। जब यही आधारभूत संरचनाएं असमय ध्वस्त होने लगें, तो केवल कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं टूटता, बल्कि जनता का शासन और प्रशासन पर विश्वास भी टूटता है।

दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़क धंसने के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संबंधित प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर को निलंबित किया तथा निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल निलंबन से समस्या का समाधान हो जाएगा? अनुभव बताता है कि अधिकांश मामलों में निलंबित अधिकारी कुछ समय बाद बहाल हो जाते हैं या उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। जिन कंपनियों को काली सूची में डाला जाता है, वे कुछ समय बाद नए नाम से फिर सरकारी ठेके प्राप्त करने लगती हैं। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार का चक्र लगातार चलता रहता है। वास्तविक समस्या जवाबदेही के अभाव की है। निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया–डिजाइन, सामग्री, तकनीकी परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय नहीं होती। जब दोषियों को कठोर दंड नहीं मिलता, तब भ्रष्टाचार को अप्रत्यक्ष संरक्षण मिल जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष बरसात के साथ सड़कें उखड़ती हैं, पुलों में दरारें पड़ती हैं और करोड़ों रुपये की परियोजनाएं समय से पहले दम तोड़ देती हैं।

देश में सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ जाता है। ठेके हासिल करने से लेकर बिलों के भुगतान तक अनेक स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब परियोजना की लागत का बड़ा भाग अवैध लेन–देन में खर्च हो जाता है, तब निर्माण की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। घटिया सामग्री का उपयोग, तकनीकी मानकों की अनदेखी और समय सीमा का दबाव मिलकर ऐसी संरचनाएं तैयार करते हैं जो पहली ही परीक्षा में असफल हो जाती हैं। विडंबना यह भी है कि प्रत्येक दुर्घटना के बाद जांच समितियां गठित होती हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, मुआवजे घोषित होते हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आता। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं। जनता का आक्रोश धीरे–धीरे शांत हो जाता है और फिर कोई नई दुर्घटना उसी कहानी को दोहरा देती है। विकसित देशों में भी दुर्घटनाएं होती हैं, किंतु वहां प्रत्येक हादसे के बाद प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं। भारत में सुधार की अपेक्षा लीपापोती अधिक दिखाई देती है।

अब समय आ गया है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। प्रत्येक परियोजना के लिए स्वतंत्र थर्ड–पार्टी गुणवत्ता ऑडिट अनिवार्य किया जाए। निर्माण सामग्री की डिजिटल ट्रैकिंग, प्रत्येक चरण का तकनीकी सत्यापन तथा ड्रोन और आधुनिक सेंसर आधारित निरीक्षण को व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। परियोजना पूरी होने के बाद केवल उद्घाटन नहीं, बल्कि निश्चित अवधि तक उसके प्रदर्शन का भी वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि दोषी अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों की व्यक्तिगत एवं आर्थिक जवाबदेही तय हो। यदि उनकी लापरवाही से जनहानि होती है या सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है, तो केवल निलंबन नहीं, बल्कि सेवा से बर्खास्तगी, आर्थिक दंड और आपराधिक मुकदमे जैसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे, आर्थिक गलियारे, हाई–स्पीड रेल, आधुनिक हवाई अड्डे और स्मार्ट शहर तभी सार्थक होंगे, जब उनकी नींव ईमानदारी, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर आधारित होगी। विकास का अर्थ केवल नई परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि उनका वर्षों तक सुरक्षित और टिकाऊ बने रहना भी है। आज आवश्यकता केवल नई सड़कें और पुल बनाने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें कोई भी सड़क पहली बारिश में न धंसे, कोई पुल उद्घाटन से पहले न गिरे और कोई हवाई अड्डा यात्रियों के लिए खतरा न बने। भ्रष्टाचार की गहरी नींव पर विकास की मजबूत इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। यदि भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना है, तो विकास की चमक के साथ उसकी गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। तभी जनता का विश्वास बचेगा, सार्वजनिक धन सुरक्षित रहेगा और विकास का मार्ग सचमुच मजबूत एवं स्थायी बन सकेगा।

बंद होते रेलवे स्टेशनों के बुक स्टॉल

– डॉ. सत्यवान सौरभ–

भारतीय रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों के आवागमन के केंद्र नहीं रहे हैं, बल्कि वे लंबे समय तक देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना के भी प्रतीक रहे हैं। किसी भी बड़े या छोटे रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करते ही व्हीलर जैसे बुक स्टॉल यात्रियों का ध्यान आकर्षित करते थे। यात्रा शुरू होने से पहले अखबार खरीदना, कोई पत्रिका चुनना या रास्ते के लिए उपन्यास लेना एक सामान्य आदत थी। रेल यात्रा और पुस्तकें मानो एक–दूसरे की पूरक थीं। लेकिन आज वही बुक स्टॉल सन्नाटे में डूबे दिखाई देते हैं। जिन स्थानों पर कभी पुस्तकों और पत्रिकाओं के खरीदारों की भीड़ लगी रहती थी, वहाँ अब गिने–चुने ग्राहक ही दिखाई देते हैं। अनेक स्टॉलों पर पुस्तकों की जगह पानी की बोतलें, बिस्कुट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और अन्य खाद्य पदार्थों ने ले ली है। यह दृश्य केवल बाजार के बदलते स्वरूप का नहीं, बल्कि समाज की बदलती पठन संस्कृति का भी संकेत है।

पिछले दो दशकों में तकनीक ने मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सूचना तक पहुँच को आसान, तेज और सुलभ बना दिया है। आज दुनिया की लगभग हर जानकारी कुछ सेकंड में मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है। समाचार, पुस्तकें, शोध–पत्र, पत्रिकाएँ, वीडियो, पॉडकास्ट और ऑडियोबुककृ सब कुछ एक ही उपकरण में समाहित हो गया है। यह तकनीकी क्रांति निस्संदेह मानव सभ्यता की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा प्रश्न भी जुड़ा है कि क्या इस डिजिटल सुविधा ने मुद्रित पुस्तकों और पत्रिकाओं की आवश्यकता को कम कर दिया है? रेलवे स्टेशनों के सूने पड़े बुक स्टॉल इस प्रश्न को और अधिक प्रासंगिक बना देते हैं।

एक समय था जब धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रविवार, हंस, सरिता, मुक्ता, गृहशोभा, वनिता, मेरी सहेली, प्रतियोगिता दर्पण, चंदामामा, मधु मुस्कान, मायापुरी, मनोहर कहानियाँ, रीडर्स डाइजेस्ट, इंडिया टुडे और आउटलुक जैसी पत्रिकाओं की नई प्रतियों का पाठकों को बेसब्री से इंतजार रहता था। रेलवे स्टेशनों के बुक स्टॉल इन पत्रिकाओं के सबसे बड़े बिक्री केंद्र होते थे। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लाखों यात्री अपनी रुचि के अनुसार पत्रिकाएँ खरीदते थे। बच्चों के लिए कॉमिक्स, युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री, महिलाओं के लिए गृह और परिवार से जुड़ी पत्रिकाएँ तथा साहित्य प्रेमियों के लिए उपन्यास और कहानी संग्रह आसानी से उपलब्ध रहते थे। यह केवल व्यापार नहीं था, बल्कि पढ़ने की एक जीवंत संस्कृति थी।

आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ बंद हो चुकी हैं। कई पत्रिकाओं का प्रकाशन सीमित हो गया है। जिनका प्रकाशन जारी भी है, उनकी प्रतियाँ पहले की तुलना में बहुत कम छपती हैं। पुस्तक विक्रेताओं का कहना है कि अब यात्रियों की पहली पसंद पुस्तक नहीं, बल्कि मोबाइल फोन है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे अधिकांश लोग किताबों की अलमारी की ओर देखने के बजाय अपने मोबाइल की स्क्रीन में व्यस्त दिखाई देते हैं।

इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण इंटरनेट को माना जाता है। इंटरनेट ने ज्ञान और सूचना को लोकतांत्रिक बना दिया है। पहले किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय जाना पड़ता था या पुस्तक खरीदनी पड़ती थी। आज वही जानकारी मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध है। हजारों पुस्तकें पीडीएफ रूप में उपलब्ध हैं। किंडल और अन्य ई–बुक प्लेटफॉर्म ने पुस्तक पढ़ने के तरीके को बदल दिया है। ऑडियोबुक ने उन लोगों के लिए भी पढ़ने का विकल्प उपलब्ध कराया है जिनके पास समय कम है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पढ़ने की आदत समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसका माध्यम बदल गया है।

लेकिन यह आधा सच है। वास्तविक चिंता पढ़ने के माध्यम से अधिक पढ़ने की प्रवृत्ति को लेकर है। डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध अधिकांश सामग्री त्वरित उपभोग के लिए तैयार की जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता का ध्यान अधिक समय तक किसी एक विषय पर टिकने नहीं देते। रील्स, शॉर्ट वीडियो और छोटे–छोटे पोस्ट लोगों को लगातार एक सामग्री से दूसरी सामग्री की ओर ले जाते रहते हैं। परिणामस्वरूप गहन अध्ययन, चिंतन और विश्लेषण की प्रवृत्ति कमजोर पड़ती जा रही है।

मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि लगातार बदलती डिजिटल सामग्री मनुष्य की एकाग्रता को प्रभावित करती है। पहले लोग एक उपन्यास या पुस्तक को कई दिनों तक पढ़ते थे। अब कुछ मिनटों से अधिक समय तक एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता जा रहा है। सूचना की मात्रा बढ़ी है, लेकिन ज्ञान की गहराई कम होती दिखाई देती है। यही कारण है कि पढ़ने और देखने के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। वीडियो देखना और पुस्तक पढ़ना दो अलग–अलग मानसिक प्रक्रियाएँ हैं। पुस्तक पाठक को कल्पना, विश्लेषण और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है, जबकि वीडियो अधिकांश दृश्य सामग्री सीधे प्रस्तुत कर देता है।

रेलवे स्टेशनों के बुक स्टॉलों की बदली हुई तस्वीर केवल तकनीक की कहानी नहीं कहती, बल्कि बदलती जीवनशैली का भी संकेत देती है। आज लोगों के पास समय कम है और व्यस्तता अधिक है। लंबी रेल यात्राएँ भी अब मोबाइल मनोरंजन का माध्यम बन चुकी हैं। पहले चार घंटे की यात्रा में एक पुस्तक पढ़ी जाती थी, अब वही समय सोशल मीडिया, वेब सीरीज, गेम और वीडियो देखने में बीत जाता है।

शिक्षा व्यवस्था भी इस परिवर्तन से प्रभावित हुई है। विद्यार्थियों का अध्ययन अब परीक्षा–केंद्रित होता जा रहा है। पाठ्यक्रम से बाहर पढ़ने की आदत लगातार कम हो रही है। विद्यालयों और महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में पहले जैसी चहल–पहल दिखाई नहीं देती। डिजिटल नोट्स और ऑनलाइन कोचिंग ने मुद्रित अध्ययन सामग्री की आवश्यकता को काफी हद तक कम कर दिया है। हालांकि यह परिवर्तन सुविधाजनक है, लेकिन इसके कारण साहित्यिक और सामान्य पठन की परंपरा कमजोर हुई है।

परिवारों में भी पढ़ने का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। कभी बच्चों को जन्मदिन पर कहानी की पुस्तकें उपहार में दी जाती थीं। घरों में छोटी–छोटी पुस्तक अलमारियाँ होती थीं। समाचार पत्र पूरे परिवार द्वारा पढ़े जाते थे। आज बच्चों के हाथों में कम उम्र से ही स्मार्टफोन और टैबलेट आ गए हैं। मनोरंजन के डिजिटल विकल्प इतने अधिक हैं कि पुस्तकें उनके सामने आकर्षण खोती जा रही हैं।

यह भी सत्य है कि प्रकाशन उद्योग स्वयं समय के अनुरूप बदलाव करने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। युवा पाठकों की बदलती रुचियों के अनुरूप सामग्री, आकर्षक प्रस्तुति और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ संतुलित रणनीति विकसित करने में देर हुई। परिणामस्वरूप सोशल मीडिया ने पाठकों का बड़ा हिस्सा अपनी ओर आकर्षित कर लिया।

हालांकि पूरी तस्वीर निराशाजनक भी नहीं है। भारत में विश्व पुस्तक मेला, जयपुर साहित्य महोत्सव, क्षेत्रीय पुस्तक मेले और साहित्यिक आयोजनों में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी यह बताती है कि अच्छी पुस्तकों के प्रति रुचि अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ऑनलाइन पुस्तक बिक्री भी लगातार बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि पाठक मौजूद हैं, लेकिन उनकी खरीदने और पढ़ने की आदत का स्वरूप बदल गया है।आज आवश्यकता पुस्तक और डिजिटल माध्यम के बीच संघर्ष खड़ा करने की नहीं है। दोनों का संतुलित उपयोग ही समय की मांग है।

चौथी औद्योगिक क्रांति की राजनीति

–मनीष तिवारी–

अमरीका के पूर्व रक्षा सचिव ने 12 फरवरी, 2002 को प्रसिद्ध रूप से कहा था कि 'जैसा कि हम जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जानते हैं कि हम जानते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जानते हैं कि हम नहीं जानते लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते।' हालांकि रुम्सफील्ड के ये शब्द सद्दाम हुसैन के शासनकाल के ईराक द्वारा विभिन्न आतंकवादी समूहों को 'सामूहिक विनाश के हथियारों' की आपूर्ति के संबंध में सबूतों के पूर्ण अभाव के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में थे। यद्यपि इस टिप्पणी ने उन्हें 2002 का 'फुट–इन–द–माऊथ' पुरस्कार (राजनीतिक अस्पष्टता की बकवास के लिए) दिलाया लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियों के विकासवादी प्रक्षेपवक्र और मानव जाति पर उनके प्रभाव के मामले में यह बहुत सटीक है। यह कहना सामान्य बात होगी कि अमरीका और चीन चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियों में अग्रणी हैं। जबकि अमरीका क्वांटम कम्प्यूटिंग, सैमी–कंडक्टर, जीनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में व्यापक रूप से आगे है, वहीं चीन इलैक्ट्रिक बैटरी, हाइपरसोनिक, सौर प्रौद्योगिकी, 6–जी नैटवर्क और ड्रोन एवं रोबोटिक्स में नेतृत्व कर रहा है। ये दोनों देश आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस, उन्नत सामग्री, क्वांटम सैंसर, मशीन लर्निंग और नैनो टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह सूची सांकेतिक है, न कि विस्तृत। हालांकि, एक व्यापक वास्तविकता की जांच अनिवार्य है। अमरीका और उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता चौथी पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के सैन्य अनुप्रयोगों के क्षेत्र में विशेष रूप से बढ़ रही है। शी जिनपिंग ने हाल ही में इस संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए यह रेखांकित किया कि क्या अमरीका और चीन 'थ्यूसीडाइड्स ट्रैप' से उबर सकते हैं और महाशक्तियों के बीच संबंधों के लिए एक नया प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं? यह फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों में अपनी बड़ी बढ़त का लाभ उठाने वाली एक संभावित जी–2 हो सकती है। मध्य शक्तियां संरचनात्मक रूप से उस महाशक्ति व्यवस्था पर निर्भर हैं, जिसकी वे आलोचना तो करती हैं लेकिन उसे बदल नहीं सकतीं। एक उदार और अंतर्राष्ट्रीयवादी व्यवस्था मध्य शक्तियों को कुछ ध्यान देने, गठबंधनों की सदस्यता देने और सैन्य और राजनयिक समर्थन के बदले में मानदंड–निर्धारण में भागीदारी की अनुमति देने के लिए तैयार थी। आज का अमरीकी प्रशासन ऐसे खाकों के प्रति तिरस्कार प्रदर्शित करता है।

ट्रम्प प्रशासन मध्य शक्तियों को थोड़ी ढील दे सकता है और वह भी केवल हाशिए पर लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के केंद्र को आकार देने के मध्य शक्तियों के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, विशेष रूप से तब जब रूत्र (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) का भूत सक्रिय रूप से वैश्विक व्यवस्था के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को फिर से डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है। जब मध्य शक्तियां और कम विकसित राष्ट्र निजी तकनीक दिग्गजों की सद्भावना और असंख्य व्यापारिक हितों पर निर्भर रहेंगे, जिनका राजस्व अधिकांश विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के जी.डी.पी. से अधिक है, तो हार्ड और सॉफ्ट पावर के संदर्भ में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने में क्या प्रभावशीलता है? हालांकि यहां भी वास्तविकता निराशाजनक है। उदाहरण के तौर पर, केवल आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस (ए.आई.) पर, चीन डाटा हब बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 295 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च करेगा। चीन ने अकेले 2025 में ए.आई. पर 98 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च किए। चीन का सरकारी खर्च 56 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

अमरीका स्थित 5 निजी कंपनियां–अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और ओरेकल–सामूहिक रूप से 2026 में 700 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करेंगी। इसकी तुलना में, भारत का ए.आई. मिशन 2025–2030 के बीच केवल 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च करेगा। फिर इतने दिखावटी ए.आई. शिखर सम्मेलन आयोजित करने का क्या उद्देश्य है।

शराब पीने से मना करने पर बेटे ने पिता को ईंट से कूंच मौत के घाट उतारा

संवाददाता—महराजगंज। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधी नगर वार्ड में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां शराब और जुए की लत से परेशान एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई।

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार गांधी नगर वार्ड निवासी हरिखमन (55 वर्ष) ठेला लगाकर मूंगफली बेचकर अपने परिवार का भरण—पोषण करते थे।

परिवार में पत्नी निर्मला, दो बेटे शेषनाथ और मनोज हैं। बताया जा रहा है कि बड़ा बेटा शेषनाथ लंबे समय से शराब पीने और जुआ खेलने का आदी था। इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था। परिजन कई बार उसे समझा चुके थे, लेकिन उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया। शनिवार रात शेषनाथ शराब के नशे में घर पहुंचा। इस दौरान पिता हरिखमन ने उसे शराब पीने और जुआ खेलने से मना किया। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि गुस्से में शेषनाथ ने अपने पिता की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट से बचने के लिए हरिखमन घर से बाहर सड़क की ओर भागे, लेकिन आरोपी बेटे ने उनका कॉलर पकड़ लिया और जोर से सड़क पर पटक दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से वह जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद भी शेषनाथ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने पास में पड़ी ईंट उठाकर पिता के सिर पर लगातार कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण हरिखमन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी शेषनाथ को मौके से ही कोतवाली ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

मृतक के भाई हरिपाल ने बताया कि हरिखमन पिछले करीब एक महीने से अपने बेटे को शराब छोड़ने के लिए लगातार समझा रहे थे। परिवार को उम्मीद थी कि वह अपनी आदतों में सुधार करेगा, लेकिन शनिवार रात विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। आरोपी शेषनाथ की शादी करीब सात वर्ष पहले हुई थी। उसके दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। इस दर्दनाक घटना से पूरा परिवार सदमे में है, जबकि मोहल्ले के लोग भी स्तब्ध हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे की लत ने एक परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया।

गांधी नगर वार्ड के लोगों के अनुसार आरोपी शेषनाथ लंबे समय से शराब और जुए का आदी था। उसकी इन आदतों को लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था। पिता हरिखमन उसे बार—बार समझाते थे कि वह नशा और जुआ छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी निभाए, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। शनिवार रात मामूली कहासुनी हिंसक झगड़े में बदल गई और बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी।

समपार फाटक की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन

संवाददाता—महराजगंज। घुघली—आनन्दनगर नई रेलवे लाइन की निर्माण के बीच घुघली के घघरुआ खंडेसर गांव के पास समपार फाटक की मांग को लेकर मामला गरमाता जा रहा है। पिछले दिनों प्रदर्शन व जीएम रेलवे को मांगपत्र देने के बाद रविवार को ग्रामीणों ने गांव में धरना दिया। प्रदर्शन करते हुए समपार फाटक बनवाने की मांग की। कहा कि समपार फाटक नहीं बना तो कई गांवों के लोगों की राह बंद हो जाएगी, जिससे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना रहा कि यह रेल लाइन घघरुआ खंडेसर गांव से होकर निकल रही है। इससे लिंक सड़क से निकली गांव की सड़क प्रभावित हो रही है। अगर यहां समपार फाटक नहीं लगाया गया तो रास्ता नहीं मिलेगा। इसी मांग को लेकर ग्रामीण राकेश बहादुर सिंह, पूर्व प्रधान जवाहर मद्धेशिया, राम क्यास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नई रेलवे लाइन पर आकर नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया। काफी देर तक धरना स्थल पर किसी सक्षम अधिकारी के न पहुंचे से ग्रामीणों ने आक्रोश जताया।

ग्रामीणों का कहना रहा कि इस गांव में रमणीक स्थल पोखरा, हनुमान मंदिर, छठ घाट, प्राथमिक व जूनियर स्कूल, कब्रिस्तान सहित अन्य स्थल मौजूद है। जब इस लिंक सड़क को रेलवे बन्द कर देगा तो इन जगहों पर आना—जाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी।

ग्रामीणों ने आगे बताया कि इस मांग को लेकर विधायक, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी व रेलवे के अधिकारियों को पत्रक दिया गया है। लेकिन अभी किसी अधिकारी के द्वारा कोई सार्थक आश्वासन नहीं मिला है। इस दौरान महेंद्र प्रताप सिंह, बैजनाथ सिंह, जयराम सिंह, यशवंत सिंह, विपिन बिहारी सिंह, केशव सिंह, मजहर अली, विदेशी, संजय सिंह, अजय सिंह, उमेश सिंह, बृजेश सिंह, नाथू प्रसाद व जमालुद्दीन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

ग्रामीणों ने धरना समपार फाटक की मांग को लेकर दिया क्योंकि फाटक न बनने पर कई गांवों के लोगों की राह बंद हो जाएगी।

रिहायशी इलाके में मुर्गी फार्म तक पहुंचा तेंदुआ, दहशत में ग्रामीण

संवाददाता—महराजगंज। सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के पकड़ी रेंज के कटहरा सेक्शन स्थित ग्राम कटहरा में रविवार सुबह एक तेंदुआ रिहायशी इलाके तक पहुंच गया। तेंदुए के मुर्गी फार्म में घुसने की सूचना मिलते ही गांव में अफरा—तफरी मच गई। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पटाखे छोड़ा और सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तेंदुए का पता नहीं चला। ग्रामीणों के अनुसार, तेंदुआ लमुहवा के किनारे स्थित जितेंद्र सिंह के मुर्गी फार्म में घुस आया था। फार्म के आसपास मौजूद लोगों की नजर पड़ते ही शोर मच गया। लोगों की आवाज सुनकर तेंदुआ वहां से निकलकर जंगल की ओर भाग गया। संतलाल, राममजन, राजू, श्रीराम, मिथिलेश सिंह, वीर बहादुर और पवन कुमार समेत अन्य ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दो दिनों से कटहरा, टोला रामनगर और आसपास के गांवों में तेंदुआ लगातार दिखाई दे रहा है। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है शाम होते ही लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। पकड़ी वन क्षेत्राधिकारी सुशांत मणि त्रिपाठी ने बताया कि तेंदुए के दिखने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि तेंदुआ दिखाई देने पर उसके पास न जाएं, उसे घेरने या भगाने का प्रयास न करें और भीड़ न लगाएं। अकेले खेत या जंगल की ओर जाने से बचें, बच्चों और मवेशियों पर विशेष नजर रखें तथा तेंदुआ दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें।

अमेरिकी नागरिक पर पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज

संवाददाता—महराजगंज। भारत—नेपाल सीमा स्थित सोनौली के पास बिना वैध दस्तावेज नेपाल जाने के प्रयास में हिरासत में लिए गए अमेरिकी नागरिक सैम ब्राउन से पूछताछ के बाद एसएसबी ने सोनौली पुलिस को सौंप दिया। अवैध रूप से सीमा पार करने के आरोप में उसके खिलाफ 14 विदेशी विषयक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। एसएसबी के मुताबिक शनिवार की सुबह करीब 10 बजे सीमा स्तंभ संख्या—516 के पास अमेरिकी नागरिक नेपाल की ओर जाने का प्रयास कर रहा था। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा। जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। कंपनी मुख्यालय लाकर पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह कैलिफोर्निया का रहने वाला है। वह अब तक करीब 70 देशों की यात्रा कर चुका है। भारत आने से पहले वह बाली गया था। करीब आठ सप्ताह पहले अमेरिका से गोवा पहुंचा था, जहां छह सप्ताह तक रुका। इसके बाद वह सोनौली आया।

पासपोर्ट के बारे में पूछताछ में अमेरिकी नागरिक ने बताया कि उसका पासपोर्ट बंगलुरू निवासी एक परिचित के पास है। उसने यह भी दावा किया कि गोवा में उसकी मुलाकात नेपाल के एक व्यक्ति से हुई थी, जिससे वह सोनौली में मिलने वाला था। पर वह दोनों व्यक्तियों का पूरा पता नहीं बता सका। अमेरिकी नेवी एवं स्पेशल फोर्सेज का पूर्व कर्मी बताते हुए उसने यह भी कहा कि दो वर्ष पहले उसने नेवी की नौकरी छोड़ दी थी। गहन पूछताछ व जांच के बाद यात्रा संबंधी वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर एसएसबी ने अमेरिकी नागरिक सैम ब्राउन को विधिक कार्रवाई के लिए सोनौली कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। सोनौली कोतवाल महेंद्र मिश्रा ने बताया कि अमेरिकी नागरिक सैम ब्राउन के खिलाफ तहरीर के आधार पर 14 विदेशी विषयक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थन ने बताया कि एसएसबी ने सोनौली के पास एक अमेरिकी नागरिक को अनाधिकृत रूप से नेपाल में प्रवेश करते समय पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि वह टूरिस्ट वीजा पर वह थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट गुम हो गया। वहां से जलमार्ग से श्रीलंका और वहां से 2 नवंबर—25 को जलमार्ग से भारत पहुंचा। तब से वह गोवा में रह रहा था। नेपाल जाने की कोशिश में पकड़े गए व्यक्ति के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। सोनौली कोतवाली में उसके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

हनुमानगढ़ी उज्जैनिया पट्टी के नए महंत बने संदीप दास, सर्वसम्मति से मिली जिम्मेदारी

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या। श्री हनुमानगढ़ी पंचांग पट्टी उज्जैनिया के महंत संतराम दास महाराज के 27 जून को साकेतवास के उपरांत रामानंदी सनातन परंपरा के अनुसार सभी धार्मिक संस्कार विधिवत संपन्न किए गए। भंडारे के पश्चात रविवार को अखिल भारतीय निर्वाणी अनी अखाड़ा के महासचिव महंत नंदराम दास महाराज के स्थान पर उज्जैनिया पट्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित नागा संतों ने सर्वसम्मति से झूंडी जमात के संत महंत संदीप दास महाराज को आजीवन उज्जैनिया पट्टी का महंत मनोनीत किया। वहीं मोहित श्रीवास्तव को पट्टी का मुख्तार चुना गया।बताया गया कि दिवंगत महंत संतराम दास महाराज डूंडा जमात से संबंधित थे। परंपरा के निर्वहन के क्रम में इस बार झूंडी जमात के महंत संदीप दास को यह दायित्व सौंपा गया। महंत संदीप दास, पूर्व गद्दीनशीन महंत रमेश दास महाराज के बड़े शिष्य हैं। हनुमानगढ़ी की पंचायती व्यवस्था के अनुरूप उज्जैनिया पट्टी के संतों ने उनके नाम पर सहमति जताते हुए उन्हें पट्टी की बागडोर सौंपी। महंत पद ग्रहण करने के बाद संदीप दास महाराज ने कहा कि हनुमानगढ़ी जी महाराज की कृपा और संत समाज के आशीर्वाद से उन्हें सेवा का यह अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की परंपराओं, नियम—नियमावली तथा पूर्व महंतों द्वारा स्थापित मर्यादाओं का पूर्ण पालन करते हुए पट्टी के कार्यों का संचालन किया जाएगा।अखिल भारतीय निर्वाणी अनी अखाड़ा के महासचिव महंत नंदराम दास महाराज ने कहा कि महंत संतराम दास महाराज के साकेतवास के बाद सभी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए संत समाज ने सर्वसम्मति से महंत संदीप दास को यह जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में उज्जैनिया पट्टी की व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी।महंत संदीप दास के गुरुभाई महंत कल्याण दास महाराज ने कहा कि गुरुदेव साकेतवासी गद्दीनशीन महंत रमेश दास महाराज के आशीर्वाद से बड़े गुरुभाई को यह दायित्व मिला है। उन्होंने संत समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि महंत संदीप दास हनुमानगढ़ी की गौरवशाली परंपराओं का निर्वहन करते हुए सनातन धर्म के प्रचार—प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।बैठक में नवनियुक्त महंत का संतों ने पुष्पमालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर महंत धर्मदास (सरपंच), महंत रामकुमार दास, वरिष्ठ पुजारी रमेश दास, राजू दास सहित उज्जैनिया पट्टी के सैकड़ों संत, महंत और नागा साधु उपस्थित रहे।

'एक पेड़ मां के नाम' महाअभियानः डीएम—नोडल अधिकारी ने किया पौधरोपण, 40 लाख का लक्ष्य

संवाददाता—देवरिया। जिले में रविवार को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया गया। प्रदेश सरकार के वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ के अंतर्गत चलाए गए इस अभियान में सरकारी विभागों, न्यायपालिका, पुलिस, शिक्षण संस्थानों, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी की। जिले में इस वर्ष 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार प्रथम और जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बैतालपुर विकासखंड के सिरजम गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और अमृत सरोवर पर पौधे लगाए। इस दौरान अंत्योदय राशन कार्डधारक परिवारों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को फलदार पौधे भी वितरित किए गए। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने गौरीबाजार क्षेत्र के पाननकुंडा और इंदुपुर स्थित अमृत सरोवरों पर भी पौधरोपण किया। कार्यक्रम के दौरान स्काउट—गाइड के छात्र—छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण और पौधों की देखभाल का संकल्प दिलाया गया। इसी क्रम में महर्षि देवरहा बाबा ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में भी श्एक पेड़ मां के नामश् अभियान के तहत एक दिन में 5,000 पौधों का वृहद पौधरोपण किया गया। प्राचार्य डॉ. रजनी के नेतृत्व में यह अभियान तीन चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण में पूर्व जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में फैकल्टी, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों ने 1,000 पौधे लगाए। दूसरे चरण में भाजपा जिलाध्यक्ष काली प्रसाद की मौजूदगी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने 1,500 पौधों का रोपण किया। अंतिम चरण में सांसद डॉ. शशांक मणि त्रिपाठी ने पौधरोपण कर अभियान में भाग लिया, जिसमें एमबीबीएस के विद्यार्थियों ने 2,500 पौधे लगाए। समापन पर प्राचार्य डॉ. रजनी ने सभी प्रतिभागियों को पौधों की देखभाल का संकल्प दिलाते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने पौधे लगाने के साथ उन्हें संरक्षित रखने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम के सफल संचालन में डॉ. प्रियंका राय, डॉ. शुभम पाण्डेय और डॉ. शालिनी गुप्ता सहित सांस्कृतिक समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। न्यायालय, पुलिस और शिक्षण संस्थानों की सक्रिय भागीदारी दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि पर्यावरण और मानव एक—दूसरे के पूरक हैं तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अर्चना ने पौधों के संरक्षण को मां के स्नेह से जोड़ते हुए वृक्षों की महत्ता बताई। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के नेतृत्व में पुलिस लाइन सहित जिले के सभी थानों और चौकियों में पौधरोपण किया गया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने छायादार, फलदार और औषधीय पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस परिवार के बच्चों को चॉकलेट और मिठाइयां भी वितरित की गई। उधर, बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वावधान में 400 पौधे लगाए गए। प्राचार्य प्रो. पी.एन. सिंह ने अभियान का शुभारंभ किया, जबकि स्वयंसेवकों और शिक्षकों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी चलाया अभियान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बरहज विधानसभा क्षेत्र के अहिल्यापुर में श्एक पेड़ मां के नामश् अभियान के तहत आम, अमरूद और आंवला के पौधे लगाए। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि पौधरोपण धरती माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। जिलेभर में पंचायत भवनों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, अमृत सरोवरों, ग्राम सचिवालयों, चारागाहों और निजी भूमि पर भी बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उनके संरक्षण को सुनिश्चित कर देवरिया को हरित और पर्यावरणीय रूप से समृद्ध बनाना है।

जन और सेवा ही था महंत दयाराम दास का जीवन संदेश, 27वीं पुण्यतिथि पर संतों ने दी श्रद्धांजलि

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या(सं)। रामनगरी की सुप्रसिद्ध पीठ परमहंस आश्रम वासुदेवघाट के संस्थापक साकेतवासी महंत दयाराम दास रामायणी महाराज को 27वीं पुण्यतिथि पर संतों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्वाचार्य महंत के पुण्यतिथि महोत्सव को परमहंस आश्रम के वर्तमान पीठाधिपति श्रीमहंत रामानंद दास रामायणी महाराज ने अपना सानिध्य और अधिकारी राम उजागर दास महाराज ने संयोजन प्रदान किया। रविवार की सुबह सर्वप्रथम मंदिर में विराजमान भगवान श्रीराम जानकी समेत अन्य देवी—देवताओं का दिव्य—भव्य श्रृंगार कर पूजन—अर्चन, आरती किया गया। भगवान को फल—मिष्ठान समेत अन्य विविध पकवानों का भोग लगा। उसके बाद मंदिर प्रांगण में स्थित संस्थापक महंत दयाराम दास रामायणी महाराज की प्रतिमा का पूजन—अर्चन, आरती किया गया। पुण्यतिथि पर संत—महंत और भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रीमहंत रामानंद दास रामायणी महाराज ने आए हुए संत—महंत, भक्तजनों का स्वागत—सत्कार कर भेंट, विदाई दिया। उन्होंने बताया कि मठ के संस्थापक महंत गुरुदेव दयाराम दास रामायणी महाराज की पुण्यतिथि निष्ठा पूर्वक मनाई गई। पुण्यतिथि पर अयोध्या धाम के सभी संत—महंत सम्मिलित हुए। जिन्होंने गुरुदेव को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उनके कृतित्व—व्यक्तित्व पर प्रकाश भी डाला। गुरुदेव अप्रतिम प्रतिभा के धनी संत रहे। जो भजन—साधना में तल्लीन रहा करते थे। वह गौ एवं संत सेवी होने के साथ—साथ भजनानंदी संत रहे। जिनका व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। सरलता तो उनमें देखते ही झलकती थी। महाराज श्री एक कुशल रामायणी थे, जिनका गणना विद्वान संतों में होती थी। विद्वता ने उन्हें महारथ हासिल था। अधिकारी राम उजागर दास महाराज ने कहा कि साकेतवासी महंत ने अयोध्यानगरी में एक विशाल आश्रम की स्थापना कर उसका कार्यभार संभाला। जिसके वह संस्थापक महंत रहे। उन्होंने मठ का सर्वांगीण विकास किया। मंदिर अपने उत्तरोत्तर समृद्धि की ओर अग्रसर है। जहां गौ, संत, विद्यार्थी, आगंतुक सेवा सुचारु रूप से चल रही है। समस्त उत्सव, समैया, त्योहार आदि परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। श्रीदयाराम दास मानस सेवा ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय, निराश्रित, दीन—दुखियों आदि की मदद और गरीब कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। पुण्यतिथि पर रामनगरी के सभी संत—महंत व मंदिर से जुड़े भक्तजन उपस्थित रहे।

मानदेय नहीं बढ़ा तो अगस्त के बाद होगा आरपार का आंदोलन —प्रदेश अध्यक्ष

संवाददाता—महराजगंज। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ की जिला स्तरीय बैठक रविवार को जिला मुख्यालय परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजवंशी शर्मा ने व संचालन जिलाध्यक्ष बिन्दू देवी ने किया। बैठक में रसोइयों के मानदेय वृद्धि, कार्य की परिस्थितियों व लंबित मांगों पर चर्चा करते हुए सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगस्त के बाद आरपार का आंदोलन होगा। प्रदेश अध्यक्ष राजवंशी शर्मा ने कहा कि बीते 25 मई को लखनऊ के यूको गार्डन पार्क में हुए विशाल धरना—प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने रसोइयों का मानदेय जल्द बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगस्त तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो प्रदेशभर की रसोइयां आरपार का आंदोलन करने को बाध्य होंगी। जिलाध्यक्ष बिन्दू देवी ने कहा कि रसोइयां विद्यालयों में साफ—सफाई के साथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराती हैं। इसके बावजूद उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। जिला महासचिव सरस्वती देवी ने चुनावी ड्यूटी में भोजन बनाने के बावजूद पारिश्रमिक नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। विजयलाल ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर सचिवालय का घेराव किया जाएगा।

इस दौरान दीनानाथ दूबे, जवाहिर कनौजिया, रीता, अशोक, केदार, गीता, अर्चना, फूलकुमारी, शांति, रेशमा, सुखिया, द्रौपदी, पुनीता, शारदा, कुसुम, आरती, शोभा, मीरा, शीला सहित बड़ी संख्या में रसोइयां मौजूद रहीं।

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान शुरू, 32 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य

संवाददाता—महराजगंज। जिले में रविवार को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से महराजगंज स्थित एसएसबी कैंप परिसर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया।

इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, एसएसबी जवानों और एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। डॉ. मिथिलेश तिवारी, उपाध्यक्ष, बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ, मुख्य अतिथि रहे।

विशिष्ट अतिथियों में जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया, मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, प्रभागीय वन अधिकारी सुर्वे निरंजन और जिला विद्यालय निरीक्षक पी.के. शर्मा शामिल थे। सभी अतिथियों ने एसएसबी कैंप परिसर में पौधे रोपे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर एसएसबी के जवान, एनसीसी कैडेट, वन विभाग के अधिकारी—कर्मचारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने श्एक पेड़ मां के नामश् अभियान के तहत अपनी मां के सम्मान में एक—एक पौधा लगाकर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। जिले में इस वर्ष 32 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशासन, वन विभाग, विभिन्न सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जिले के विभिन्न स्थानों पर यह पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पौधारोपण केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देने का माध्यम है। उन्होंने लोगों से पौधों की नियमित देखभाल करने की भी अपील की।

सोलर कंपनी में नौकरी का झांसा,21 करोड़ का साइबर फ्रॉड, पूर्व बीजेपी नगर मंत्री समेत 5 गिरफ्तार

संवाददाता—गोंडा। पुलिस और साइबर सेल ने रविवार को अंतरराज्यीय साइबर ठगी का खुलासा किया है। जिसमें पूर्व भाजपा ओबीसी मोर्चा नगर मंत्री विजय सोनी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में अब तक 20 से अधिक खातों से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेनदेन हुआ है। आरोपी बेरोजगार युवकों को सोलर कंपनी में नौकरी और सैलरी अकाउंट खुलवाते थे। इन्हीं खातों को 'म्यूल अकाउंट' बनाकर देशभर में निवेश ठगी, डिजिटल अरेस्ट और सेक्सटॉर्शन जैसे साइबर अपराधों से हासिल करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जाते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व भाजपा ओबीसी मोर्चा नगर मंत्री विजय सोनी, दीपक गोयल, देवनारायण मिश्रा, गंगोत्री पांडेय और शाहबान आलम उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 15 आधार कार्ड, 10 सिम कार्ड, 8 मोहरें, दो दोपहिया वाहन और विभिन्न फर्मों के फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। मामला देहात कोतवाली का है।

मामले की शुरुआत सिसई टिकरिया निवासी वीरेंद्र प्रताप और सत्यम तिवारी की शिकायत से हुई। दोनों ने देहात कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उन्हें सोलर कंपनी में नौकरी और 15 हजार रुपए वेतन का लालच दिया गया। 21 फरवरी को विजय सोनी और दीपक गोयल उन्हें प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की बड़गांव शाखा ले गए, जहां सैलरी अकाउंट खोलने की बात कही गई। लेकिन बैंक कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से उनके नाम पर श्री श्याम इंटरप्राइजेज के नाम से करंट अकाउंट खोल दिया गया। पीड़ितों का आरोप है कि खाते में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर आरोपियों ने नेट बैंकिंग का पूरा नियंत्रण अपने पास रख लिया। 21 फरवरी से 6 मार्च के बीच इन्हीं खातों से आरटीजीएस के जरिए करीब ढाई करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। बाद में बैंक पहुंचने पर उन्हें पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी हुई।

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह पहले बेरोजगार और जरूरतमंद लोगों को नौकरी का झांसा देता था। इसके बाद उन्हें सोनू मोबाइल एंड कंप्यूटर कैफे ले जाकर फर्जी उद्यम पंजीकरण, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेज तैयार कराए जाते थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अलग—अलग बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे। कई मामलों में बैंक ऑफ बड़ौदा समेत अन्य बैंकों में भी फर्जी फर्मों के नाम पर खाते खोले गए। आरोपी खाताधारकों को यह विश्वास दिलाते थे कि यह उनका सैलरी अकाउंट है, जबकि खाते का पूरा एक्सेस अपने मोबाइल नंबर और नेट बैंकिंग के जरिए खुद संचालित करते थे। बाद में इन्हीं खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध से प्राप्त रकम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए श्म्यूल अकाउंटश् के रूप में किया जाता था। पुलिस के अनुसार दस्तावेजों से अब तक 20 से अधिक म्यूल खातों का पता चला है। इन खातों से 21 करोड़ रुपए से अधिक का लेनदेन किया गया। एनसीआरपी पोर्टल पर इन खातों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना सहित कई राज्यों से 43 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस अब तक 3.20 करोड़ रुपए फ्रीज करा चुकी है।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह इन खातों का इस्तेमाल निवेश के नाम पर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन और अन्य साइबर अपराधों से वसूली गई रकम को ट्रांसफर करने के लिए करता था। इसके बदले आरोपी मोटा कमीशन लेते थे। प्रारंभिक जांच में कई राज्यों से जुड़े साइबर अपराधियों के साथ इनके संपर्क के भी संकेत मिले हैं। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपियों ने भोले—भाले लोगों को सोलर कंपनी में नौकरी और सैलरी अकाउंट का झांसा देकर उनके नाम पर करंट अकाउंट खुलवाए।

सीएम योगी ने गोरखपुर से किया 35 करोड़ पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ, 'एक पेड़ मां के नाम' का दिया संदेश

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखपुर से, एक दिन में 35 करोड़ रिकार्ड पौधरोपण के लक्ष्य वाले प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भगवानपुर टोल प्लाजा के समीप पवित्र त्रिवेणी (नीम, पीपल, बरगद) का पौधा लगाया और सेल्फी भी ली। इसके बाद पौधरोपण महायज्ञ के उपलक्ष्य में गीडा सेक्टर 28 में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत नौ वर्षों में प्रदेश में भौतिक विकास की रफ्तार तेज होने के साथ ही वनाच्छादन का भी विस्तार हुआ है। पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करने के बाद गोरखनाथ मंदिर वापस लौटते समय सीएम योगी ने आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे भी पौधरोपण किया। यहां उन्होंने मौलश्री का पौधा लगाया।

विज्ञापन गीडा के सेक्टर 28 में हुए पौधरोपण महायज्ञ कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। एक्सप्रेसवे, हाईवे के साथ बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछा है। नए–नए उद्योग लगे हैं। शहरीकरण का दायरा बढ़ा है और नई–नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं। भौतिक विकास में तेज योगदान देने वाले इस राज्य ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्पित प्रयासों से वनाच्छादन के विस्तार में भी सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती पर जब एक पेड़ उगता है तो वह सैकड़ो टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है।

उन्होंने बताया कि विगत नौ वर्षों में यूपी का वनाच्छादन बढ़ने से 6 करोड़ 37 लाख 74 हजार 130 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण तथा 4 करोड़ 63 लाख 90 हजार 130 टन ऑक्सीजन उत्सर्जन हुआ। ताया और इसमें हर व्यक्ति की तरफ से योगदान दिए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि धरती माता हम सबको अच्छा वातावरण देती हैं। आगे बढ़ने का अवसर, पेट भरने को अन्न, अच्छे–अच्छे फल, पीने के लिए जल देने के साथ घर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। धरती माता के बारे में हमारे ऋषियों ने संकल्प के भाव से कहा है, श्माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्यारूश अर्थात यह धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पुत्र के रूप में धरती माता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' का आह्वान किया है। यह आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुंदर बनाने का राष्ट्रीय कर्तव्य है।

सीएम योगी ने पौधरोपण के थीम 'एक पेड़ मां के नाम' को बहुत सुंदर बताते हुए कहा कि मां हर व्यक्ति, हर जीव के लिए दुनिया की सबसे सुंदर उपहार होती है। उन्होंने कहा कि हम खुद के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं लेकिन सबकुछ देने वाली धरती माता के स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हैं। खुद की आरोग्यता के लिए हम सभी को धरती माता की आरोग्यता का ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनंतकाल तक जीवसृष्टि बनी रहे, इसके लिए पौधरोपण अत्यंत आवश्यक है। इसी के दृष्टिगत पौधरोपण महाभियान की शुरुआत की गई है।

उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष 5 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। नौ वर्ष में अब तक प्रदेश में 242 करोड़ पौधरोपण किया जा चुका।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण पर मंडरा रहे संकट का प्रभाव मौसम चक्र पर भी पड़ा है। हाल के दिनों में जो बारिश शुरू हुई है, उसे 15 जून से प्रारंभ हो जाना चाहिए था। बारिश करीब महीने भर लेट है। जो बीज 15 जून तक लग जाना चाहिए था यदि उसे 15 जुलाई को लगाएंगे तो उत्पादन में 25 से 30 प्रतिशत तक अंतर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण असंतुलन से कभी गर्मी चरम पर पड़

रही है तो कभी सर्दी। दुनिया के अंदर लगातार ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी दी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में समुद्र के किनारे बहुत सारे शहर डूबने की स्थिति में होंगे तो कहीं जल का भीषण संकट भी हो जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सर्दियों के मौसम में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां गैस चौंबर जैसी स्थिति बन जाती है। वहां अलर्ट जारी करना पड़ता है कि बुजुर्ग, बीमार और बच्चे घर से बाहर न निकलें, जरूरी हो तो मास्क लगाकर निकलें। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि आखिर यह भैया वह स्थिति पैदा ही क्यों हुई? इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही देते हुए कहा, 'प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया। अंधाधुंध पेड़ काटे गए। जल का दोहन किया गया लेकिन जल संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। तालाबों पर अवैध कब्जे हो गए। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, आज उसकी कीमत विश्व मानवता को चुकानी पड़ रही है।' मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में जब डबल इंजन की भाजपा सरकार प्रदेश में बनी तब हैलोजन लाइटों को हटाकर उसकी जगह पर्यावरण अनुकूल एलईडी स्ट्रीट लाइट लगवाने का अभियान शुरू किया गया। प्रदेश में 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई, इससे प्रदेश सरकार को 100 करोड रुपये की बचत भी हुई।

साथ ही हैलोजन जलने के दौरान उसमें मरने वाले कीड़े–मकोड़े के भयंकर बदबू से भी मुक्ति मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। बताया कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना, लोगों के बिजली बिल को आधा कर दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी का नया स्रोत लोगों को उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के विजन से देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं जो पहले कांग्रेस की सरकार में ब्लैक होते थे। देश में 10 करोड़ परिवारों में माताओं, बहनों को रसोई के धुएं से मुक्ति मिली है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ परिवारों को यह लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भी इसके बारे में आह्वान किया है। सीएम योगी ने बताया कि अयोध्या धाम प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनी है। वहां जितनी भी स्ट्रीट लाइट जलती है, उसमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें न सिर्फ पौधे लगाने हैं बल्कि उनका रखरखाव और देखभाल भी करना है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अपने खेत में पेड़ लगाए हैं उन्हें कार्बन क्रेडिट फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत पैसा भी प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति से 'एक पेड़ मां के नाम' पौधरोपण अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया। अपील की कि अपने परिवार के सदस्यों की स्मृति में, परिवार के सदस्यों के नाम से और पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनें। पौधरोपण महायज्ञ 2026 के अवसर पर आयोजित जनसभा के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश के नौ वर्ष की हरित गाथा' लघु फिल्म और 'वानिकी कैलेंडर' का विमोचन किया। लघु फिल्म में यूपी में पिछले नौ वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों और हासिल उपलब्धियों को दर्शाया गया है। जबकि वानिकी कैलेंडर में वर्ष 2026–27 के लिए वन विभाग की कार्ययोजना का उल्लेख है।

पौधरोपण महायज्ञ कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने पौधों का वितरण किया। साथ ही उन्होंने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना के अंतर्गत खेत के किनारे अधिक पौधरोपण करने वाले किसानों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लाभार्थी गीता देवी, मधुरा, इशरावती, शीला, कालिंदी को घर के सामने लगाने के लिए सहजन का पौधा भेंट किया। जबकि, कार्बन क्रेडिट योजना के तहत 700 से अधिक पौधरोपण करने वाले नरपति (कैम्पियरगंज गोरखपुर), 650 से अधिक पौधरोपण करने वाले अशफाक खान (देसही देवरिया), 800 पौधों का रोपण करने वाली रंजना देवी (हाटा कुशीनगर) और 850 पौधे लगाने के लिए अरविंद कुमार (पडरौना कुशीनगर) को मुख्यमंत्री के हाथों कार्बन क्रेडिट के लिए मिलने वाली रकम का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। पौधरोपण महायज्ञ के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन में यूपी में ग्रीनरी बढ़ी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार देश में ग्रीनरी वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश प्रगति करते हुए अब दूसरे स्थान तक पहुंच चुका है।

वन मंत्री ने कहा कि आज के पौधरोपण के पूर्ण होते ही यूपी में पिछले दस साल पौधरोपण की कुल संख्या 275 करोड़ हो जाएगी। इस बार के पौधरोपण महाभियान में तीस प्रतिशत फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी का आह्वान किया अपने घर पर मां के साथ मिलकर या मां की स्मृति एक पौधा जरूर लगाएं। वन मंत्री ने बताया कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित वानिकी विश्वविद्यालय के निर्माण की शुरुआत जल्द ही की जाएगी।

पौधरोपण महायज्ञ के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। वह सदैव लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसी विजन के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने एक दिन में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में यूपी का इतना विराट विकास हुआ है जितना कोई सोच भी नहीं सकता।

सीएम योगी का स्वागत करते हुए सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में सहजनवा विधानसभा का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। उन्होंने नौ वर्षों में जितना विकास किया, वह सौ वर्षों में भी नहीं हो पाता। प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील कुमार चौधरी ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद, राज्यसभा सदस्य संगीता यादव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, महेंद्रपाल सिंह, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, पौधरोपण महायज्ञ के लिए गोरखपुर के नोडल अधिकारी सुहास एलवाई, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

29.78 लाख पौधरोपण, 'एक पेड़ मां के नाम' और 'सेल्फी भेजो' अभियान शुरू

संवाददाता–संतकबीरनगर। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से रविवार को वृक्षारोपण महायज्ञ–2026 का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एक ही दिन में वन विभाग और विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से कुल 29.78 लाख पौधे रोपे गए।

बघौली विकासखंड के बरईपार गांव में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने पवित्र हरिशंकरी (पीपल, पाकड़ और बरगद) का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम थीम पर आधारित अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, मेंहदावल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी, जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। मुख्य अतिथि चारु चौधरी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपने जन्मदिन, विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। उन्होंने वृक्षारोपण को सेवा और उसकी रक्षा को साधना बताया।

मेंहदावल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने वृक्षों को प्रकृति का अमूल्य उपहार बताते हुए लोगों से पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल का भी संकल्प लेने का आह्वान किया। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने भी अधिक से अधिक पौधरोपण करने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की।

इसी अभियान के तहत जगद्गुरु शंकराचार्य विद्यालय इंटर कॉलेज, मेंहदावल में वन विभाग द्वारा हरित वसुन्धरा वृक्षारोपण संकल्प महाअभियान आयोजित किया गया। यहां विद्यार्थियों को पौधे वितरित किए गए और पौधा लगाओ, सेल्फी भेजो और पुरस्कार पाओ अभियान शुरू किया गया।

वन विभाग ने घोषणा की कि पौधरोपण कर निर्धारित क्यूआर कोड पर सेल्फी भेजने वाले चयनित विद्यार्थियों को आगामी 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) पर सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कौशलेंद्र सिंह, वृंदावन दूबे, बेलहर कलां के रेंजर, प्रभागीय वनाधिकारी हरिकेश यादव, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार प्रभात द्विवेदी और उपजिलाधिकारी हृदय राम तिवारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अवकाश के दिन भी शिक्षकों ने निभाई जिम्मेदारी, विद्यालयों में हुआ व्यापक पौधरोपण

संवाददाता–गोरखपुर। प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ के तहत जिले के विद्यालयों में रविवार को बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया। अवकाश होने के बावजूद बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक विद्यालय परिसरों में पहुंचे तथा छात्र–छात्राओं के साथ मिलकर पौधे लगाए। बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 18 हजार पौधे, जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 15,900 पौधों का रोपण किया। विद्यालय परिसरों में नीम, पीपल, बरगद सहित पर्यावरण के लिए उपयोगी एवं छायादार पौधे लगाए गए। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पौधों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में उनकी भूमिका के बारे में भी जानकारी दी। शिक्षकों ने संकल्प लिया कि पौधारोपण के साथ इन पौधों की नियमित देखभाल भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आने वाले वर्षों में ये पौधे विकसित होकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

पुलिस ने रोका तो भड़के मुकेश साहनी, बोले- मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, कहीं भी जाने का अधिकार है

संवाददाता–गोरखपुर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआइपी (विकासशील इंसान पार्टी) के प्रमुख मुकेश साहनी को रविवार को महराजंज से गोरखपुर पहुंचने पर असुरन चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद पुलिस उन्हें नौका विहार स्थित होटल ले गई। प्रशासन ने उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। मुकेश सहनी गोरखपुर क्लब परिसर स्थित आशीष मैरिज हाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, लेकिन प्रशासन द्वारा पूर्व में ही कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर दी गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए मुकेश ने कहा कि वह पूरे प्रदेश में रात्रि प्रवास कर रहे हैं और एक भारतीय नागरिक होने के नाते उन्हें देश में कहीं भी आने–जाने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने होटल संचालकों पर दबाव बनाया और कार्यक्रम स्थल को सील कर दिया। उन्होंने कहा, मैं बिहार का पूर्व मंत्री हूं, फिर भी मेरे साथ किसी अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। गोरखपुर में अपने समर्थकों से मिलने तक से रोका जा रहा है।

उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर संविधान की भावना के विपरीत काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में संघर्ष करेगी। उन्होंने निषाद समाज की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आगामी चुनाव को लेकर पार्टी उचित समय पर निर्णय लेगी।

बुआ पर गलत तरीके से भूमि का बैनामा कराने का आरोप

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के रेहरा गांव में एक भूमि से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता ने अपने ही बुआ पर गलत तरीके से बैनामा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई की मांग की है।रेहरा गांव निवासी मोहम्मद आरिफ ने एसपी समेत अन्य अधिकारियों के अलावा आईजीआरएस के माध्यम से दर्ज कराई शिकायत में बताया है कि स्व. बाबा मोहम्मद सईद ने 1989 में गाटा संख्या 228 और 615 की भूमि मौखिक हिब्बानामा के जरिए उनके व उनकी मां शमीमुन्निसा के नाम कर दी थी। आरोप है कि बुआ ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गाटा संख्या 615 की भूमि का हिस्सा अन्य लोगों के साथ मिलकर सात लाख रुपये में अवैध रूप से बेच दिया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पिता के दो भाई व चार बहनें थी। चारों बहनों की शादी बाबा ने पिता के जीवित रहते कर दिया और चारों बहने अपने ससुराल रहने लगी। उसके पिता मो.शकील की मृत्यु बाबा मोहम्मद सईद के जीवित रहते हो गई थी इस कारण बाबा मुहम्मद सईद की संपत्ति के जीवित जायज वारिस वह व उसकी माता समीमुन्निशा की थी। पिता के मृत्यु के बाद उसकी बड़ी बुआ के मन में लालच आ गया। 11 मई 2009 को बुआ ने गाटा संख्या 228 ख व गाटा संख्या 615 का नुमाइशी एवं फर्जी बैनामा करा लिया। जिसकी जानकारी हमें हुई तो तीन जून 2009 को बैनामा की नकल निकाल कर सिविल जज (जू.डि.) बांसी में वाद दाखिल किया जो हस्तांतरित होकर सिविल जज (जू.डि.) डुमरियागंज में विचाराधीन हैं। बैनामा के आधार पर बुआ ने तहसीलदार डुमरियागंज में धारा 34 एलआर एक्ट दाखिल किया। जिसमें वह व उसके माता शमीमुन्शिा ने आपत्ति जताई। 19 अप्रैल 2010 को तहसीलदार न्यायालय ने खारिज दाखिल को स्थगित करते हुए उसके कायमी प्रार्थनापत्र स्वीकार कर दिया। आदेश का इन्द्राज नकल खतौनी में कर दिया। मामला राजस्व परिषद लखनऊ में भी चल रहा है जिसमें स्थगन आदेश पारित है। जानकारी बुआ को बखूबी है। बैनामें की मंसूखी का वाद सिविल जज (जू.डि.) डुमरियागंज में विचाराधीन है बावजूद इसके तथ्यों को छिपाते हुए उसके व उसके मां की सम्पत्ति को जालसाजी पूर्ण तरीके से हड़पने की नियत से मेरी बुआ निवासी नगर पंचायत डुमरियागंज ने बभनी माफी निवासी एक व्यक्ति को दो बीघा जमीन बिना खतौनी में नाम दर्ज हुए बेच दिया। पीड़ित आरिफ ने डुमरियागंज थाने व एसपी से शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि मामले की जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

चोर का अस्तित्व खत्म होता है, मंदिर का नहीं –संजय निषाद

संवाददाता–संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने रविवार देर शाम बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। डॉ. निषाद ने कहा कि किसी भी चुनाव में जीत की सबसे बड़ी ताकत बूथ का कार्यकर्ता होता है। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया।

डॉ. संजय निषाद ने सम्मेलन में निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के अधिकारों की लड़ाई लगातार जारी है और वे सदन में एक वकील की तरह इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि समय आने पर निषाद समाज को आरक्षण का लाभ अवश्य मिलेगा।

राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, षम–राम हैं और मंदिर–मंदिर है। किसी घर में चोरी हो जाने से घर का अस्तित्व खत्म नहीं होता, बल्कि चोरी करने वाले का अस्तित्व खत्म हो जाता है।ष उन्होंने यह भी कहा कि चंदा चोरी के मामले में पकड़े गए लोगों को कानून और संविधान के अनुसार उनके अपराध के अनुरूप कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना की। डॉ. निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि चंदा चोरी के आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा गया है और कानून के तहत उन्हें सजा भी मिलेगी।

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर डॉ. संजय निषाद ने कहा, षनिषाद जिस नाव पर बैठता है, उसे डूबने नहीं देता। हम जिसके साथ रहते हैं, पूरी ईमानदारी से रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, और 2027 में भाजपा गठबंधन फिर से सरकार बनाएगा। उन्होंने बताया कि पिछली बार गठबंधन को मिली 16 सीटों में से निषाद पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी उन सीटों पर भी जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जहां पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था।

45.65 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, रंगाराव बोले– सिर्फ पौधे लगाना नहीं, उनकी देखभाल भी जरूरी

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। रविवार को 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण महायज्ञ–2026 के तहत एक वृहद पौधरोपण अभियान चलाया गया। नौगढ़ विकास खंड के धौरीकुईयां स्थित समय माता मंदिर परिसर में इस अभियान का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह, कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य, प्रमुख सचिव पुनर्गठन समन्वय, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन तथा जिले के नोडल अधिकारी एसवीएस रंगाराव, डीएम शिवशरणप्पा जीएन, एसपी डॉ. अभिषेक महाजन, सीडीओ बलराम सिंह और डीएफओ नीला एम सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह, विधायक श्यामधनी राही, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य और नोडल अधिकारी एसवीएस रंगाराव का स्मृति चिह्न और पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित मनमोहक गीत प्रस्तुत किए। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पहल पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों का पालन–पोषण करती है, उसी प्रकार पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

जसवंत सिंह ने कहा कि केवल पौधे लगा देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि उन्हें जीवित रखने के लिए नियमित देखभाल और पोषण आवश्यक है। उन्होंने वृक्षारोपण को पर्यावरण को संतुलित रखने का सबसे प्रभावी उपाय बताया, क्योंकि पेड़ हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सिद्धार्थनगर में निर्धारित लक्ष्य से अधिक पौधे लगाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और यह अभियान मुख्यमंत्री के प्रिय जनपद में सफल होगा। कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि वन विभाग की ओर से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिद्धार्थनगर पिछड़े जनपद की पहचान से निकलकर अग्रणी जनपद बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' लगाने का संकल्प दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। सभी को संकल्प लेना चाहिए कि वे एक पौधा जरूर लगाएंगे। मुख्यमंत्री एक संकल्प के साथ पूरे प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।

भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री की पहल पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोगों को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल संचयन और जल संरक्षण के लिए भी पेड़ बेहद जरूरी हैं। वृक्षों से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और लोगों को शुद्ध हवा व ऑक्सीजन मिलती है। प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य प्रमुख सचिव पुनर्गठन समन्वय, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन तथा जिले के नोडल अधिकारी एसवीएस रंगाराव ने कहा कि शासन ने पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर को 45 लाख 65 हजार 400 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। जिले में लक्ष्य से अधिक पौधे लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बारिश समय पर होती थी, लेकिन अब सामान्य से कम बारिश हो रही है। बदलते पर्यावरण और जलवायु संतुलन को देखते हुए वृक्षारोपण की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसमें हरित क्षेत्र को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। रंगाराव ने कहा कि पौधे जीवन का आधार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 'एक पेड़ मां के नाम' जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह, विधायक श्यामधनी राही, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य, नोडल अधिकारी एसवीएस रंगाराव, अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार जताया। इस कार्यक्रम में डुमरियागंज सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल, नौगढ़ ब्लॉक प्रमुख रेनू मिश्रा, एसडीएम नौगढ़ राहुल सिंह, डीसी मनरेगा संदीप सिंह, पीडी अनिल कुमार, वन विभाग की एसडीओ बीना तिवारी, बीडीओ नौगढ़ समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

200 लोगों ने ली नशामुक्ति की शपथ

संवाददाता–संतकबीरनगर। खलीलाबाद तहसील अंतर्गत सेमरियावां विकासखंड में ड्रग मुक्त जन अभियान के तहत एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। अहमद शिक्षण संस्थान, छाता में रविवार को हुई। इस बैठक में तिलजा और बजहरा न्याय पंचायतों के गांवों के दो सौ से अधिक लोगों ने नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। प्रगति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस अभियान की अध्यक्षता राष्ट्रीय संयोजक एवं यूथ आइकन अवार्डी प्रदीप सिसोदिया ने की। प्रदीप सिसोदिया ने कहा कि नशे की समस्या केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि संस्कारों और पारिवारिक जागरूकता से समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर नशेड़ी नहीं बनता, बल्कि गलत संगति, तनाव और सामाजिक परिस्थितियों के कारण इसकी चपेट में आ जाता है। सिसोदिया ने नशे के कारण बढ़ती घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं, चोरी, छिनैती और अन्य अपराधों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नशे से कई परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं और युवा पीढ़ी, जिसमें युवतियां भी शामिल हैं, मादक पदार्थों की गिरफ्त में आ रही है।

उन्होंने विभिन्न धर्मों का उदाहरण देते हुए बताया कि सभी प्रमुख धर्म नशे से दूर रहने की सीख देते हैं, और धार्मिक व नैतिक शिक्षा ही समाज को इस बुराई से बचा सकती है। उन्होंने परिवारों से अपने बच्चों को संस्कार देने और नशे में लिप्त लोगों को समझाने की जिम्मेदारी उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान अहमद शिक्षण संस्थान की कक्षा 10 की छात्रा गायत्री चौहान ने उपस्थित लोगों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, दूसरों को इसके प्रति जागरूक करेंगे, और अपने घर तथा प्रतिष्ठानों पर ष्हमें गर्व है कि मेरा परिवार नशा मुक्त हैष का स्टीकर लगाएंगे। प्रदीप सिसोदिया ने सरकार की नशा मुक्ति योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि नशे या मानसिक परेशानी से संबंधित सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14414 का उपयोग करें। उन्होंने जोर दिया कि समाज के सहयोग और जन–जागरण से ही ड्रग कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com